भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 792

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजेरियन सेक्शन प्रसव पर नियंत्रण

792. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2021 में आईआईटी मद्रास के अध्ययन के निष्कर्षों की जानकारी है, जिसमें कहा गया है किभारत में 21.5 प्रतिशत बच्चों का जन्म, निजी अस्पतालों में 49.7 प्रतिशत की उच्च दर के साथ, सिजेरियन सेक्शन (सी-सेक्शन) के माध्यम से किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;

(ग) क्या सरकार ने निजी अस्पतालों में सीजेरियन सेक्शन प्रसव की इस उच्च दर के कारणों का विश्लेषण किया है औरयदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;

(घ) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसा के अनुरूप सीजेरियन सेक्शन प्रसव की दर को, विशेषकर निजीअस्पतालों में 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक रखने हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है औरयदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सी-सेक्शन केवल चिकित्सकीय रूप से आवश्यक होने पर करना सुनिश्चित करने और अनावश्यक सी-सेक्शनके जोखिमों के बारे में रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु कोई तंत्र/प्रणाली मौजूद है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार आईआईटी मद्रास द्वारा वर्ष 2021 में किए गए अध्ययन के निष्कर्षों से अवगत है, जिसमें देश भर में, विशेष रूप से निजी और सरकारी अस्पतालों में सीजेरियन सेक्शन (सी-सेक्शन) के प्रचलन का विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4 और एनएफएचएस-5) के दो दौरों के बीच, पांच वर्ष के अंतराल में पाए गए रुझानों पर प्रकाश डाला गया है।

(ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पीआरसी)-जेएसएस आर्थिक अनुसंधान संस्थान धारवाड़, कर्नाटक की रिपोर्ट के अनुसार "अंडरस्टेंडिंग दि कनटेक्सट ऑफ सीजेरियन डिलिवरी फरॉम दि प्रोवाइडर्स एंड रिसीवर्स प्रस्पेक्टिव" के संबंध में किए गए अध्ययन में देश में सी -सेक्शन डिलीवरी की दर में वृद्धि के पीछे निम्नलिखित मुख्य कारणों का उल्लेख किया गया है;

- डॉक्टर द्वारा नैदानिक निर्णय-निर्धारण: मां की आयु, एक से अधिक गर्भधारण, भ्रूण को संकट, पिछला सी-सेक्शन, लंबा प्रसव समय, प्लेसेंटा प्रीविया, साथ ही मां को होने वाली परेशानियों जैसे नैदानिक संकेतों में सीजेरियन डिलीवरी की संभावना अधिक होती है।
- रोगी/समुदाय की प्राथमिकताएँ: इस मामले में निर्णय-निर्धारण में इनकी भूमिका होती है।

(घ) से (च)राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निगरानी तंत्र की स्थापना सहित उच्च सी-सेक्शन दरों से संबंधित उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न उपाय/पहलें की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

- सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों के लिए सामान्य प्रसव की तुलना में सीजेरियन सेक्शन द्वारा कराए गए प्रसव के अनुपात के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित करना अपेक्षित है।
- स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों में डेटा रिपोर्टिंग और निगरानी को मजबूत किया गया है।
- लक्ष्य पहल के तहत, सभी सरकारी अस्पतालों के लिए प्रसूति ओटी के लिए लक्ष्य मूल्यांकन चेकलिस्ट में एक समर्पित सी-सेक्शन ऑडिट घटक शामिल किया गया है।
- सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में सुप्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दक्ष, दक्षता, कुशल जन्म परिचारक (एसबीए) और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी (एनपीएम) सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

******